नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने की तैयारी

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लंबे समय से कल्याण और विकास के बीच संतुलन खोजती रही है. वर्ष 2005 में शुरू हुई मनरेगा ने संकट के समय करोड़ों ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम आय सुरक्षा दी, लेकिन दो दशक बाद यह भी सच है कि बदलते समय, बढ़ती आकांक्षाओं और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी. इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया 'विकसित भारत - जी राम जी बिल, 2025' एक बड़ा और दूरगामी कदम माना जा सकता है.

इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश स्पष्ट है,ग्रामीण रोजगार अब केवल राहत नहीं, बल्कि विकास का औजार होगा. 100 दिनों की जगह 125 दिनों की रोजगार गारंटी देना सिर्फ संख्या बढ़ाने का फैसला नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण आय, उपभोग और स्थानीय बाजारों को गति देने की रणनीति है. महंगाई और अनिश्चित मौसम के दौर में यह अतिरिक्त 25 दिन ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन सकते हैं.नए बिल का दूसरा बड़ा बदलाव इसका विजन और स्वरूप है. 'विकसित भारत, रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)' नाम ही यह संकेत देता है कि सरकार अब मनरेगा को केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रखना चाहती. लक्ष्य है कि ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण जो वर्षों तक गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें. पक्की सड़कें, जल संरक्षण ढांचे, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं खेती को बाजार से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं. तकनीक के मोर्चे पर भी यह बिल मनरेगा से एक कदम आगे जाता दिखता है.

बायोमेट्रिक हाजिरी, जीपीएस आधारित निगरानी और एआई के जरिए धोखाधड़ी की पहचान,ये प्रावधान उस आलोचना का जवाब हैं, जो वर्षों से फर्जी मस्टर रोल और भ्रष्टाचार को लेकर होती रही है. यदि ये प्रणालियां जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू होती हैं, तो पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों में सुधार संभव है.योजना के चार प्रमुख स्तंभ,जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका ढांचा और जलवायु लचीलापन,ग्रामीण भारत की वास्तविक जरूरतों को दर्शाते हैं.

खासकर जल संरक्षण और जलवायु लचीलापन ऐसे क्षेत्र हैं, जो आने वाले दशकों में खेती और जीवन दोनों के लिए निर्णायक साबित होंगे. सूखा, बाढ़ और असमय बारिश से जूझते गांवों के लिए यह दीर्घकालिक निवेश है.एक व्यावहारिक पहलू यह भी है कि फसल के पीक सीजन में काम रोकने की अनुमति दी गई है. इससे खेती और मजदूरी के बीच संतुलन बनेगा और किसानों को समय पर श्रमिक मिल सकेंगे. यह व्यवस्था ग्रामीण श्रम बाजार में अनावश्यक तनाव को कम कर सकती है.हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं. सबसे बड़ा सवाल वित्तपोषण को लेकर है. केंद्र और राज्यों के बीच खर्च के बंटवारे पर सहमति बनना जरूरी होगा. यदि राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा, तो योजना की गति प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, तकनीकी व्यवस्थाओं की सफलता डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे पर निर्भर करेगी.

कुल मिलाकर, विकसित भारत-जी राम जी बिल मनरेगा का विकल्प भर नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक नई विकास कथा लिखने की कोशिश है. यदि नीति और क्रियान्वयन के बीच की खाई पाट ली गई, तो यह योजना 2047 के विकसित भारत की नींव गांवों से मजबूत कर सकती है. सवाल अब यह नहीं कि बदलाव जरूरी था या नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह बदलाव जमीन पर उतनी ही मजबूती से उतर पाएगा....?

ग्वालियर चंबल डायरी

रोड टैक्स छूट में देरी से मेला व्यापारियों की बढ़ी चिंता, तैयारी पर असर

हरीश दुबे

करीब सवा सौ वर्ष की शानदार विरासत रखने वाले ग्वालियर व्यापार मेला के प्रारंभ होने में अब बमुश्किल एक हफ्ता बचा है लेकिन मेला में बिकने वाले वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट को लेकर असमंजस बरकरार है.
स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मेला प्राधिकरण के कर्ताधर्ताओं, व्यापारियों से लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे सैलानियों द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि जब सब कुछ तय है तो राज्य शासन द्वारा रोड टैक्स में रियायत का गजट नोटिफिकेशन जारी करने में विलम्ब क्यों ? यह भी संदेह उपज रहा है कि राजस्व में घाटा रोकने के लिए क्या जानबूझकर देर से यानि आधा मेला बीतने के बाद ही यह छूट देने की प्लानिंग पहले से तय कर ली गई है. मेला व्यापारी अपनी चिंताओं से सीएम और सिंधिया दोनों को वाकिफ करा चुके हैं. दोनों की तरफ से ठोस आश्वासन मिला है. बीते रोज प्रभारी मंत्री सिलावट इसी मसले पर सीएम से मिले हैं. सांसद भारत सिंह ने भी सीएम को चिट्ठी लिखी है. अब यह हर साल का रिवाज बन गया है कि ग्वालियर मेला शुरू तो 25 दिसंबर से शुरू हो जाता है लेकिन रोड टैक्स में छूट का फरमान भोपाल से देर से आता है.

पिछले मेले में भी यही हुआ था, 14 जनवरी को केबिनेट बैठक में मोहर लगने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था जबकि मेला सेक्टर में ऑटोमोबाइल कारोबारी अपने शोरूम और परिवहन विभाग अपना दफ्तर पहले ही खोल चुके थे. सच्चाई यह है कि करीब डेढ़ दशक पहले तक दी जाने वाली सेल्स टैक्स छूट जीएसटी आने के बाद बंद किए जाते ही यह राष्ट्रीय स्तर का मेला सिर्फ खेल तमाशे और सॉफ्टी, पापड़ तक ही सीमित होकर रह गया है. वाहनों की खरीद पर दी जाने वाली रोड टैक्स छूट ही मेला की कुछ रौनक बचाए है और अब उसमें भी हील हवाला हो रहा है.

औपचारिकता में सिमट गया तानसेन समारोह

संगीतधानी ग्वालियर की फिज़ाएँ पिछले चार दिन से सुरों की बारिश से सराबोर हैं. विश्व स्तर की ख्याति रखने वाला शास्त्रीय संगीत का शीर्षस्थ महोत्सव 'तानसेन संगीत समारोह' जो चल रहा है. उपनगर ग्वालियर की तंग गलियों में स्थित तानसेन की समाधि पर प्रवाहित हो रही इस सुर सरिता का समापन कल शुक्रवार के रोज मुरार देहात के बेहट ग्राम में स्थित संगीत सम्राट की जन्मस्थली पर होना है. देशभर के सुरसाधक एवं संगीत रसिक ग्वालियर में डेरा जमाए हैं, जिन्हें पूरे साल इस आयोजन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है. देश-विदेश से आए ब्रम्हनाद के शीर्षस्थ साधक तो सुर सम्राट को स्वरांजलि दे ही रहे हैं. मूर्धन्य संगीतज्ञ पं. राजा काले व पं. तरुण भट्टाचार्य तानसेन अलंकरण से विभूषित किए गए हैं. सरकार और प्रशासन ने अपने स्तर पर आयोजन की भव्यता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब वह पहले जैसी बात नहीं रही जब देर शाम से तड़के तक यहां संगीत सभाएं चलती थीं, कार्यक्रम में जाने शहर भर से निःशुल्क बसें चलती थीं. विशाल पंडाल में बैठने तक के लिए जगह नहीं मिलती थी और चार पांच दिन के लिए पूरा शहर संगीतमय हो जाता था.

अमित शाह के आने से पहले ही उद्योग क्षेत्र में फील गुड

तानसेन समारोह निबटने की ओर है. व्यापार मेला की तैयारियां मंथर गति से चल ही रही हैं. इस बीच प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ा टारगेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर को हो रहे ग्वालियर दौरे और 'मध्य प्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025' को कामयाब बनाने का है. चूंकि इस दौरान सीएम सहित प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, लिहाजा प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं. यह समिट 5 घंटे तक चलना है और अमित शाह दोपहर करीब 2 से 3 घंटे तक इस ग्रोथ समिट में शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दो वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही इस समिट को निर्विघ्न बनाने कलेक्टर ने अफसरों की जिम्मेदारियां मुकर्रर कर दी हैं, एक बड़ी तैयारी बैठक भी हो चुकी है. अमित शाह ग्वालियर आते रहे हैं. पिछली मर्तबा वे सिंधिया की मेजबानी कुबूल कर महल भी गए थे. बहरहाल, कार्यक्रम के लिए मेला ग्राउंड में टेंट लगने लगा है. मेला ग्राउंड के चारों ओर एक किलोमीटर का एरिया 'रेड जोन' घोषित है. 500 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात करने की तैयारी है. इस क्षेत्र के इंडस्ट्रीज एरिया में कामकाज धीमा पड़ने के बाद एमपी ग्रोथ समिट 2025 से ग्वालियर चंबल ने काफी उम्मीदें लगाई हैं. उद्योग क्षेत्र फील गुड महसूस कर रहा है क्योंकि ग्वालियर अंचल में मैन्यूफैक्चरिंग, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर में बड़े निवेश के द्वार खुल सकते हैं.

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025

उच्च शिक्षा को नई दिशा दे रही सरकार

प्रो. मनोज कुमार तिवारी
(डायरेक्टर आईआईएम,मुंबई)

> यह बिल उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के व्यापक विजन में अपने योगदान को गहरा करने के लिए एक सक्षम माहौल प्रदान करता है. आखिर में कहें तो, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 एक दूरदर्शी सुधार है जो स्वायत्तता और जवाबदेही, इनोवेशन और इंटेग्रिटी, विकास और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाता है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस कानून को एक सुसंगत, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक रचनात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है. उच्च शिक्षण संस्थान इस विकसित हो रहे ढांचे के भीतर काम करने, उत्कृष्टता बनाए रखने, प्रतिभा का पोषण करने और एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत में आजादी के बाद से शिक्षा की औपनिवेशिक मानसिकता वाले ढांचे में लगातार सुधार किये जाते रहें हैं,जिसमें नई शिक्षा नीति-2020 एक अभिनव प्रयास रहा है और अब उच्च शिक्षा में सुधारों की यह यात्रा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 के साथ और आगे बढ़ाई जा रही है. हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 को संसद में पेश किया है. बिल पर अभी संसद में गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है.

प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए), एक प्रमुख संस्थान के रूप में, एकीकृत, टेक्नोलॉजी-संचालित ढांचे के तहत मानक-निर्धारण, एक्रीडिएशन और रेगुलेशन को मिलाकर इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने की एक पहल है. उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, यह प्रक्रियात्मक अनावश्यकताओं को कम करने और शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है. निश्चित रूप से यह बिल भारत की उच्च शिक्षा सुधार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. ऐसा इसलिये भी कह सकते हैं कि देश के करीब 37 करोड़ युवाओं के ज्ञान संवर्धन में अब जिस गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की जरूरत है उसके लिये एक मजबूत शैक्षिक ढ़ांचा बनाना होगा. यह बिल जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनायेगा जिससे जिससे पूर्ण पारदर्शी और टेक्नोलॉजी आधारित ढ़ांचा तैयार होगा.

पिछले कुछ दशकों में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जिसमें एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय और हजारों उच्च शिक्षण संस्थान चार करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य संवारने में अहम योगदान दे रहे हैं. वैसे तो इस शैक्षिक विस्तार से पहुंच बढ़ी है, लेकिन फिर भी कई वैधानिक निकायों के अस्तित्व के कारण नियामक विखंडन और अतिव्यापी अनुपालन आवश्यकताओं की समस्या भी पैदा हुई है.

यह बिल यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 के तहत संवैधानिक जनादेश पर आधारित है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के विज़न के साथ मिलकर, उच्च शिक्षा के समन्वित, पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर एक मुकाम रखने वाले रेगुलेशन के लिए एक मजबूत नींव रखता है. प्रस्तावित ढांचा समय के अनुसार और प्रगतिशील दोनों है, जिसमें हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम में अकादमिक उत्कृष्टता, संस्थागत स्वायत्तता और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण को काफी मजबूत करने की क्षमता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित लाइट बट टाइट रेगुलेटरी ढांचे पर बिल का जोर, व्यापक उच्च शिक्षा क्षेत्र की शैक्षिक एकरूपता, पारदर्शिता और नवाचार को दृढता के साथ लागू किये जाने पर है. यह फोकस को निर्देशात्मक नियंत्रण से हटाकर सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण द्वारा समर्थित परिणाम-आधारित निगरानी पर स्थानांतरित करके, प्रस्तावित ढांचा जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देता है.

फेसलेस, टेक्नोलॉजी युक्त सिंगल-विंडो सिस्टम की ओर यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के लिए दक्षता, निष्पक्षता और प्रशासनिक बोझ में कमी आयेगी. सबसे जरूरी बात यह है कि यह बिल राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की मौजूदा स्वायत्तता की स्पष्ट रूप से रक्षा करता है. साथ ही विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समग्र नियामक माहौल को भी मजबूत करता है. अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिये प्रस्तावित स्टैंडर्ड्स काउंसिल, रेगुलेटरी काउंसिल और एक्रेडिटेशन काउंसिल एक मजबूत नियंत्रण और संतुलन बनाते हैं जो शैक्षणिक मानकों को बनाये रखने के साथ संस्थागत विभिन्नता और नवाचार को भी बढ़ावा देता है. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर-विषयक शिक्षा, अनुसंधान-आधारित शिक्षण और उद्योग-संबंधी कौशल विकास को बढ़ावा देने के विज़न को भी पूरा करता है.

सोशल मीडिया के प्रदूषण से संसद भी घबराई

सोशल मीडिया के प्रदूषण का आतंक पूरे देश में तहलका मचा रहा है. संसद भी इससे घबरा गई है. हालत यह है कि अब इस प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग सांसद ही कर रहे हैं. उनकी चिंता है कि यदि तुरंत इस पर रोक नहीं लगी, तो हमारे पारिवारिक संबंध तहस-नहस हो जाएंगे. राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने राज्यसभा में डिजिटल प्रदूषण की शिकायत करते हुए सरकार से कहा कि इसके खिलाफ एक कानून बनाया जाए. भारत में इस समय लगभग एक अरब से अधिक मोबाइल ग्राहक हैं और इसमें भी स्मार्ट फोन का यूज करने वाले करीब 70 करोड़ लोग हैं. एक यूजर हर माह 30 जीबी तक डेटा अनुमानित उपयोग करता है. भारत के कम से कम 60 प्रतिशत बच्चे अपने माता-पिता का फोन उपयोग करते हैं और उसमें वह या तो गेम खेलते हैं या फिर रील देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं या उन साइटों को सर्च करते हैं, जो उनके माता-पिता आम तौर पर यूज करते हैं. 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों-किशोरों के पास अपने फोन हैं, जिसमें उन्होंने लॉक लगा रखा होता है या फिर वह क्या करते हैं इसकी जानकारी उनके माता-पिता के पास समयाभाव के कारण नहीं होती. सर्वाधिक चिंता इस बात की है कि यही बच्चे अब फेसबुक, गूगल, व्हाटसअप जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्म पर रील देखने, प्रसारित करने, सूचना आदान-प्रदान करने में अपना समय खर्च कर रहे हैं. मदन राठौड़ ने कहा कि आज जो रील-शॉर्ट वीडियो दिखाए जा रहे हैं, उनमें देवर-भाभी, भाई-बहन, पिता-बेटी, बहू-ससुर जैसे पवित्र रिश्तों को अशोभनीय तरीके से पेश किया जा रहा है. इन्हें बड़े ही नहीं मासूम बच्चे तक देखते हैं. सोचिए, जब बच्चे असंसदीय भाषा में अश्लील कंटेंट देखकर बड़े होंगे, तो उनके मन में पवित्र रिश्तों के प्रति क्या सम्मान रहेगा? आज बच्चे अब मोबाइल पर कार्टून नेटवर्क की दुनिया में नहीं जाते, वह न तो सिनचैन को देखते हैं, न ही मोटू-पतलू. मोबाइल हाथ में आते ही वह सीधे रील पर जाते हैं और कब घंटों हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. ऐसी हालत में समाज और आने वाली पीढ़ियों की सामाजिक सुरक्षा कौन करेगा? कैसे बचेंगे पारिवारिक मूल्य? यही चिंता भविष्य में एक नई चुनौती लेकर आ रही है.

-मनोज वार्ष्णेय

निशानेबाज

प्रधानमंत्री बनेगा कोई मराठा वीर पृथ्वीराज छोड़ रहे हवा में तीर

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पिता के जीवित रहते उत्तराधिकारी की चर्चा नहीं करते. इतने पर भी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि 19 दिसंबर को राजनीतिक भूकंप आएगा और एक मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा. बताइए कि वह मराठी व्यक्ति कौन है?'

हमने कहा, 'ऐसी बेतुकी बातों पर भरोसा मत कीजिए. इतिहास की किताब में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो अवसर नहीं चूकते थे. मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें फोड़ दी थीं लेकिन उनके पास शब्दवेधी बाण चलाने की अनोखी क्षमता थी. पृथ्वीराज के साथी व चारण चंदबरदाई ने कहा- चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुलतान है, मत चूके चौहान. इसके बाद मोहम्मद गोरी के घंटा बजाते ही ध्वनि की दिशा में पृथ्वीराज चौहान ने विपक्षी नेताओं को भी तो कुछ काम चाहिए. इसीलिए छोड़ते हैं हवा में तीर तीर छोड़ दिया. वह बाण लोहे के 7 तवे छेदकर सीधे मोहम्मद गोरी की छाती में जा धंसा. अब

जिन पृथ्वीराज चव्हाण की बात आप कर रहे हैं वह तीर नहीं, बल्कि तुक्का छोड़ रहे हैं. मोदी सरकार को नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू की पार्टियों का आधार मिला हुआ है, इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव तक मोदी ही पीएम बने रहेंगे.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, पृथ्वीराज चव्हाण ने अमेरिका में पढ़ाई की थी. वह मनमोहन सिंह की सरकार के समय पीएमओ में थे. उन्हें दिल्ली से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था. उनकी मां प्रेमलता उर्फ काकी चव्हाण राज्य में कांग्रेस की बड़ी नेता थीं. उन्होंने किसी न किसी आधार पर भूकंप आने की चेतावनी दी होगी.' हमने कहा, 'भूकंप बिना बताए अचानक आता है और वैज्ञानिक उसकी तीव्रता सीस्मोग्राफ से रिक्टर स्केल पर नापते हैं. पृथ्वीराज चव्हाण कोई वैज्ञानिक नहीं हैं. वह खयालों में हंगामा कर रहे हैं और दूर की कौड़ी ला रहे हैं. उनकी बात गंभीरता से मत लीजिए. मोदी को आरएसएस का पूरा सपोर्ट है. आप चाहें तो संघ को बीजेपी का पिता कह सकते हैं. आरएसएस पहले जनसंघ का पालक था. अब वह 45 वर्षों से बीजेपी का गार्जियन है. इसलिए पृथ्वीराज चव्हाण की एक हफ्ते में 2 बार की गई भविष्यवाणी पर भरोसा मत कीजिए. हवा में तीर छोड़ने वाले को वीर मानने की गलती मत कीजिए.'

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12114 - डॉ. सागर खादीवाला

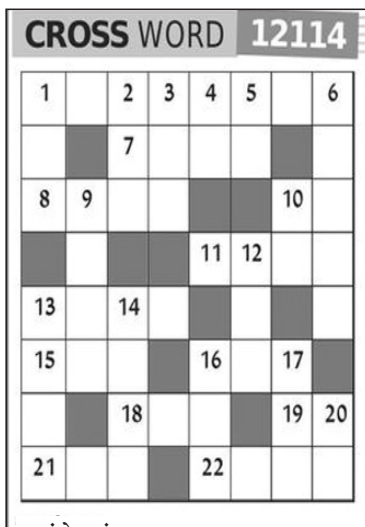

ऊपर से नीचे
1. ओज भरा, कांति युक्त 2. जानकार, ज्ञाता (उर्दू) 3. मुंह चिढ़ाना 4. नाड़ी 5. पैर, पांव, पदाघात 6. जिसका सिर झुका हुआ हो (स.) 9. रोजगार, व्यापार (उर्दू) 10. कविता 12. जड़ता, स्थिरता 13. रविवार 14. भय, खौफ (उर्दू) 16. कामयाब 17. रंगशाला में 19 20 घटनाओं का प्रदर्शन, अभिनय-ग्रंथ 20. एक प्रकार का शरबत जो आम या इमली से बनाया जाता है.

बाएं से दाएं
1. अमेरिका में गगनचुंबी इमारतों को ध्वस्त करके आतंक फैलाने के आरोप में चर्चित व्यक्ति जो बाद में मारा गया 7. किसी व्यक्ति पर रखा जाने वाला पहरा, हवालात 8. मानना, मंजूरी, ग्रहण या अंगीकार करना 10. कार्य, प्रयोजन, व्यवसाय 11. तितर-बितर, उल्टा-पुलटा, छिन्न-भिन्न 13. पूजा, उपासना, वंदना (उर्दू) 15. भांति, प्रकार (उर्दू) 16. तंग करना, कष्ट पहुंचाना 18. भला आदमी, सज्जन (उर्दू) 19. बूंद के टपकने का शब्द 21. चांदी 22. आग सुलगना, लहराना

Solution 12113

वि	श्वा	मि	त्र		वि	रा	म
च		श		पु	नी	त	
र	वा	न	गी		त	रा	श
ण		री		दु		नी	र
	द		सा	म	र्थ्य		ण
वि	शा	ला	क्षी			सं	
फ			दा	रा	शि	को	ह
ल	ल	का	र		प्रा	ची	र

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में आर्थिक योजनाओं में सुधार होगा. मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वर्ष के मध्य में भाईयों के सहयोग से शत्रु पक्ष परास्त होगा. वाहन पशु आदि से लाभ होगा. आर्थिक क्षेत्र में कमी के कारण योजनायें बाधित होंगी. वर्ष के अन्त में वाणी में कठोरता तथा क्रोध बना रहेगा. प्रियजनों के कारण हानि हो सकती है.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को वाहन पशु आदि का लाभ होगा. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखकर कार्य करना हितकर रहेगा. शत्रु वर्ग परास्त होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को आर्थिक योजनाओं में वृद्धि होगी. सिंह राशि के व्यक्तियों को प्रियजनों की वाणी में कठोरता तथा क्रोध बना रहेगा. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को आर्थिक कार्यों में सावधानी रखनी चाहिये. मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को समय लाभदायक रहेगा. यात्रा में उठाईगीरों से सतर्कता बांछनीय. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को परिजनों का अच्छा खासा सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक मिलनसार, न्यायप्रिय, परोपकारी, तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अध्ययन लेखन के कार्यों में रूचि रहेगी, ऐसा जातक इंजीनियरिंग, वायुयान संबंधी तकनीकी के कार्यों में सफल होते है.

उदयकालीन ग्रह चाल

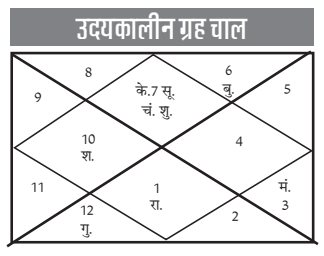

पंचांग

रा.मि. 27 संवत् 2082 पौष कृष्ण चर्तुदशी गुरूवासरे रात 4/36, अनुराधा नक्षत्रे रात 8/23, धृति योगे दिन 4/5, विष्टि करणे सू.उ. 6/47, सू.अ. 5/13, चन्द्रचार वृश्चिक, शु.रा. 8, 10, 11, 2, 3, 6 अ.रा. 9, 12, 1, 4, 5, 7 शुभांक- 0, 3, 7.

व्यापार भविष्य

पौष कृष्ण चर्तुदशी को अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से मूँग, ज्वार, बाजरा, आदि के भाव में तेजी होगी, धनु के भाव में उठाव आयेगा, सोने के भाव में समता रहेगी, रूई, सूत, कपास, में घटाबढ़ी की धारणा होगी. भाग्यांक 3578 है.

मेष- नई योजनाओंसे खर्च पर अच्छा लाभ होगा, अधिकारियों से बना कर चलें, राज सम्मान एवं यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शुभ संदेश मिलेगा.

वृषभ- भावनात्मक संबंधों में गतिरोध बना रहेगा, राजकीय मामलों में पक्ष मजबूत होगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मानसिक प्रसन्नता रहेगी.

मिथुन- कानूनी मामले मिलबैठकर सुलझा लेंगे, व्यापारिक संबंधों में स्थितरता रहेगी, अज्ञातभय, से चिन्ता रहेगी, पूजा पाठ धर्मकर्म में रूचि रहेगी.

कर्क- मनमौजी रवैया तरक्की में बाधक हो सकता है,बेचारिक मतभेद दूर होंगे, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में काम की अधिकता रहेगी.

सिंह- नए संपर्कों का लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में अड़चनें आने से अशांति होगी, व्यापार में अनुकूलता रहेगी, निजी कार्यों में व्यस्तता रहेगी.

कन्या- अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने में सफल होंगे, प्रियजनों से विरोध होगा, संयम से कार्य करना हितकर रहेगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें.

तुला- निजी कार्यों को पूरा करने में किसी की मदद लेना पड़ेगी, पारिवारिक क्लेश एवं चिन्ता रह सकती है, संतान संबंधी कार्यों में विलंब होगा, शांति से काम लें.

वृश्चिक- वैभव विलासिता के कार्यों में खर्च होगा, अप्रत्याशित लाभ होने से हर्ष रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, नियोजित कार्यो कीरूपरेखा पर विचार होगा.

धनु- आलोचना करने से बचें, घरेलू मामलों को लेकर चिन्ता होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, धार्मिक कार्य बनेंगे, स्वजनों का सहयोग मिलेगा.

मकर- पारिवारिक माहौल मेंसामंजस्य बना रहेगा, व्यापार की नई योजना बनेगी, प्रियजनों का सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण कामकाज बनेगा.

कुम्भ- नई योजना की शुरूआत में सफलता मिलेगी, खोई प्रतिष्ठा हासिल कर लेंगे, किये गये प्रयास सार्थक होंगे, निजी पुरूषार्थ बना रहेगा, संयम रखें.

मीन- अधिकारी कार्यशैली से नाराज हो सकते हैं, समय देखकर कार्य करना अच्छा रहेगा, नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, कामकाज में सफलता मिलेगी.

SUDOKU 7246

4							1	8
			6	7				2
			8					
	8	5						
	2			1			7	
						3	5	
					5			
1				4	7			
9	6							4

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7245

1	9	7	4	8	6	2	3	5
4	5	3	9	1	2	7	6	8
2	6	8	7	3	5	9	1	4
5	3	1	2	7	9	4	8	6
9	2	4	8	6	1	5	7	3
7	8	6	5	4	3	1	9	2
3	4	9	6	2	7	8	5	1
6	7	2	1	5	8	3	4	9
8	1	5	3	9	4	6	2	7